International Journal of Home Science 2019; 5(2): 169-170

ISSN: 2395-7476
IJHS 2019; 5(2): 169-170
© 2019 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 29-03-2019
Accepted: 30-04-2019

पूनम पाण्डेय
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

कामिनी जैन
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

नीलमा कुँवर
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Correspondence
पूनम पाण्डेय
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

आदिवासी महिलाओं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रभाव

पूनम पाण्डेय, कामिनी जैन, नीलमा कुँवर

सारांश
आदिवासी विकास वर्तमान संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। ब्रिटिश शासन में इसका महत्व कुछ भी नहीं था। स्वतन्त्रता के पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य अवधारणा के साथ आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास का महत्व बहुत बढ़ गया। संसदीय शासन प्रणाली में जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र का पूर्ण विकास चाहता है। संवैधानिक आधार पर भी आदिवासी विकास को प्राथमिकता दी गयी है।

कुटशब्दः आदिवासी महिलाओं, मध्य प्रदेश सरकार

प्रस्तावना
आदिवासी समाज को विस्थपन, बिखराव एवं विपन्नता से रोकने के लिए आवश्यक है कि गांव के स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, परिवहन, संचार, सड़क, ब्याज रहित ऋण सुविधा जुटाकर आत्मनिर्भर बनाना होगा यह प्रयास स्वाधीन सरकार द्वारा विभिनन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए निरन्तर जारी है। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि इन कल्याणकारी योजनाओं के सार्थक परिणाम सामने आये हैं और आ रहे हैं परन्तु कल्याण कार्यक्रम की बड़ी मात्रा में सफलता एवं अप्रभावकारी रहने के पीछे विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्ट एवं कुछ वैश्लेषिक अध्ययन से स्पष्ट है कि नीवनताओं को ग्रहण करने में जनजातीय स्वयं बाधक बनी हुई है।

अध्ययन पद्धति
शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश का जिला होशंगाबाद है जिसमें केसला ब्लाक के छीतापुर, चांदकिया एवं कासदाखुर्द गाँव को चयनित किया गया है। 100 महिला आदिवासी महिलायें प्रत्येक गाँव से चयनित की गयी हैं। इस प्रकार कुल 300 आदिवासी महिलाओं को चयनित किया गया है।

परिणाम

सारिणी 1: व्यवसाय

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	नौकरी	9	3.0
2.	व्यापार	25	8.3
3.	मजदूरी	108	36.0
4.	कृषि	87	29.0
5.	अन्य	71	23.6
	कुल	300	99.9

आदिवासी समुदाय जो कि कहीं–कहीं घुमक्कड़ जीवन जीने को मजबूर होते हैं तो कहीं–कहीं स्थाई रूप से निवास करते हैं। उनके जीवन यापन हेतु वे कौन सी क्रियाओं में संलग्न जब उनसे जानकारी लेनी चाही तो मात्र 3.0 प्रतिशत ही ऐसे थे जो कि नौकरी में संलग्न है इन पर भी सम्भवतः सरकारी प्रयासों का ही प्रभाव है। वहीं 8.3 प्रतिशत व्यापार में संलग्न हैं अर्थात वस्तुओं को बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे महुआ, लकड़ी एवं अन्य जंगली वस्तुएं आदि। वहीं 36.0 प्रतिशत आज भी

दीनहीन अवस्था में ही हैं अर्थात मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं 29.0 प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न हैं और लगभग 23.0 प्रतिशत अन्य कार्य कर रहे हैं।

सारिणी 2: आदिवासियों के विकास की योजनायें केवल लक्ष्यपूर्ति वाली

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	224	74.6
2.	नहीं	76	25.3
	कुल	300	99.9

74.6 प्रतिशत जानते हैं कि यह सत्य हैं कि योजनायें केवल लक्ष्यपूर्ति तक ही हैं जबकि 25.3 प्रतिशत ऐसा नहीं मानते उनका मानना है कि योजनाएं लाभप्रद हैं।

सारिणी 3: आदिवासी महिलाओं का जीवन स्तर उठा है, उसमें सरकारी योजनाओं का सहयोग

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	169	56.3
2.	नहीं	131	43.6
	कुल	300	99.9

आदिवासी लाभार्थियों से जब यह पूछा गया कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि जिन आदिवासी महिलाओं का जीवन स्तर उठा है, उसमें सरकारी योजनाओं का सहयोग है तो 56.3 प्रतिशत मानती हैं कि हाँ वास्तव में इन योजनाओं का प्रभाव उनके जीवन स्तर पर पड़ रहा है वहीं 43.6 प्रतिशत मानती हैं कि नहीं इसके लिए अन्य कारण जिम्मेदार हैं जैसे कि पहले से ही उनका आर्थिक रूप से सक्षम होना आदि जिसके कारण पूर्णताः इन योजनाओं की सफलता को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। किन्तु फिर भी सरकारी प्रयासों की सराहना करनी होगी क्योंकि निश्चित ही महिलाओं की स्थिति जोकि पहले बदतर थी आज स्वावलम्बी होती जा रही हैं एवं अन्य आदिवासी महिलायें उनसे प्रेरणा ले रही हैं।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलाओं में निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम मर्यादि भोपाल के माध्यम से अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। प्रमुखतः स्वाबलम्बन योजना, वसुन्धरा योजना, पवन पुत्र योजना, मधुवन डेयरी योजना, वनजा योजना, निर्मित योजना, फोटो कोपियर, एसटीडी पी0सी0ओ0, नौकायन योजना, स्टाम्प बेन्डर योजना, ट्रैक्टर योजना, ट्रैक्टर ट्राली योजना, धनवन्तरी योजना आदि हैं।

सुझाव

1. जनसमुदाय को सेवाओं के समस्त कार्यक्रमों की जानकारी दिए जाने के लिए इसको प्रचारित–प्रसारित कराये जाने हेतु कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन होना चाहिए।
2. इसके साथ ही योजना में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। योजना की जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु दृश्य श्रव्य माध्यम जैसे टी0वी0, वीडियो, चलचित्र, नाटिकायें आदि का प्रयोग होना चाहिए।

संदर्भ

Tiwari PD. Nutritional problems in rural India. Northen Book Centre, New Delhi, 2002.
Sharma Prayag. Trible Society in a flue (An Anthroposociological Study of Raika, 2006.